आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 04.12.2024
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल सितंबर से अक्टूबर के बीच 60 वर्ष की आयु की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया।
- विद्यालयी शिक्षा विभाग जल्द ही प्रवक्ता संवर्ग में 599 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती करेगा।
- देहरादून में आगामी 12 से 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो–2024 का आयोजन किया।

लोकसभा

लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक–2024 पारित कर दिया। इस विधेयक के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम–1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम–1949, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम–1955, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम–1970 और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम–1980 को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से प्रत्येक बैंक खाते में नॉमिनी की संख्या वर्तमान एक से बढाकर चार करने का विकल्प दिया गया है। विधेयक ऑडिटर के पारिश्रमिक का फैसला करने के लिए बैंकों को अधिकार प्रदान करेगा।
विधेयक प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से बैंकिंग क्षेत्र में संचालन मजबूत होगा और ग्राहक सुविधा बढेगी।

पेंशन वितरण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर के बीच 60 वर्ष की आयु की आयु पूरी करने वाले कुल 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। राज्य में पहली बार 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही राज्य के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सलीकरण होने से वृद्धजनों को समय से पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बारह सौ से बढ़ाकर पन्द्रह सौ किया है।

गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूरी होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद, जिस वर्ष माह में आवेदक की आयु साठ वर्ष होगी, उसी माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू कर दी जाएगी।

स्वीकृति

उत्तरकाशी के भटवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 शैय्यायुक्त उपजिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

रफ्लेक्टर टैग

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत सड़कों में घूम रहे आवारा पशुओं को दुर्घटना से बचाने के लिए चम्पावत जिले के टनकपुर और बनबसा में रिफ्लेक्टर टैग लगाये जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत अभी तक 200 से अधिक पशुओं को रिफ्लेक्टर टैग लगाए जा चुके हैं। जिले के यातायात प्रभारी ज्योति प्रकाश ने बताया कि आवारा पशुओं में रिफ्लेक्टर काऊ बेल्ट बांधी जा रही है, जिससे दुर्घटनाओ पर अंकुश लगेगा।

अनुरोध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुखों और प्रधान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियो ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिलापंचायतों में अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाये जाने की भांति ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को भी विकास खंडों और ग्राम सभाओं में प्रशासक के रूप में नामित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

अतिथि शिक्षक तैनाती

विद्यालयी शिक्षा विभाग जल्द ही प्रवक्ता संवर्ग में 599 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती करेगा। ये नियुक्तियां कला संकाय में की जाएंगी। इसे लेकर शासनदेश जारी कर दिया गया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इन सभी अतिथि प्रवक्ताओं को दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में तैनाती दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी है।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आयोजन

देहरादून में आगामी 12 से 15 दिसंबर के बीच होने 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो–2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 40 से अधिक देशों के विशेषज्ञों सहित छह हजार से अधिक डेलीगेट्स शामिल होंगे। आयोजन में आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने पर विचार–विमर्श किया जाएगा। इस आयोजन को 40 देशों के 20 अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्पीकर के साथ ही विभिन्न सत्रों में 150 से अधिक वक्ता संबोधित करेंगे। आयोजन में छह हजार से अधिक डेलीगेट्स के सामने परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित 900 से अधिक पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आयुष ड्रग्स निर्माता के साथ ही बॉयर सेलर मीट का भी आयोजन किया जाएगा।

इमरजेंसी ट्रोमा केयर नेटवर्क

प्रदेश में इमरजेंसी ट्रोमा केयर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र की ओर से राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। देहरादून में आयोजित बैठक के दौरान स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर उत्तराखंड, एम्स ऋषिकेश और हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के समन्वय से आपातकालीन स्थिति मे गंभीर रूप से घायल मरीजों को तत्काल बेहतर इलाज देने के विचार साझा किये गये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की कार्यकारी निदेशक स्वाति.एस भदौरिया ने आपातकालीन स्थिति में आम व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप पर जोर दिया। उन्होंने विशेष ट्रॉमा ट्रेनिंग के संवेदीकरण और पैरामेडिक्स स्टाफ के ट्रॉमा केयर के संदर्भ में प्रशिक्षण दिये जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। श्रीमती भदौरिया ने एक ऐसा ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए, जिससे आपात्कालीन स्थिति मे घटना स्थल के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल स्टाफ को अलर्ट प्राप्त हो जाये ताकि प्रभावितों को पूर्व मे ही तैयारी के साथ त्वरित उपचार प्रदान किया जा सके।

पशु कल्याण बोर्ड बैठक

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरी क्षेत्रों में निराश्रित गौवंशीय पशुओं की संख्या की समीक्षा, उनकी निगरानी और उन्हें गौसदनों में भेजने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की गौसदनों के निर्माण से सम्बन्धित बैठक में मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग की ओर से नगर क्षेत्रों स्थापित किए जाने वाले 36 गौसदनों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीमती रतूड़ी ने पंचायती राज विभाग को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 26 गौसदनों के निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू करने कोकहा। इसके लिए विभाग को मिसिंग लिंक के माध्यम से 10 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

ऋण वितरण निर्देश

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्वरोजगारपरक गतिविधियों के लिए प्राथमिकता के साथ ऋण देने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में वित्त सचिव ने कहा कि ऋण देने में सार्वजनिक सैक्टर के बैंकर्स का प्रदर्शन, निजी सैक्टर के बैंकों के मुकाबले बहुत ही असंतोषजनक है, जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए कि सार्वजनिक सैक्टर के बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका को समृद्ध करने के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।

अब एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर–

सभी समाचार पत्रों ने आज अलग–अलग ख़बरों को अपने मुख्य पृष्ठ में स्थान दिया है।

राष्ट्रीय सहारा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है– हर जिले में 31 दिसंबर तक नियुक्त करें अधिकारी, यौन उत्पीड़न कानून लागू करने में खामियों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, राज्यों को दिया निर्देश।

उत्तराखंड में बनेगा इमरजेंसी ट्रॉमा केयर नेटवर्क। इस शीर्षक के के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र का कहना है कि हादसे के घायलों को तत्काल उपचार देने के लिए कवायद, एम्स सहित बड़े अस्पतालों का लिया जाएगा सहयोग।

शैक्षिणक यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करने की ख़बर को अमर उजाला ने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। समाचार पत्र के अनुसार शैक्षणिक यात्राओं में छात्राओं के साथ महिला शिक्षिका का होना जरूरी होगा।

दूरस्थ इंटर कॉलेजों में पढाई सुचारू करांएगे 599 अतिथि शिक्षक। इस ख़बर पर दैनिक जागरण विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धनसिंह रावत के हवाले से लिखता है– विद्यालयों में नहीं होगी शिक्षकों की कमी, पठन–पाठन होगा सुचारु।

बैकों द्वारा राज्य में सरकारी योजनाओं पर ऋण बांटने की ख़बर पर दैनिक अमर उजाला लिखता है– ऋण बांटने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कंजूस, निजी बैंको से पिछड़े। निजी के पचासी फीसदी की तुलना में सीडी रेशो सिर्फ बयालिस फीसदी, सचिव वित्त ने सीडी रेषो में सुधार के लिए माइक्रो प्लानिंग और गहन समीक्षा के दिए निर्देश।